मैरी चंद्र शेखर राव

बनाम

संकायाध्यक्ष, सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज एवं अन्य

2 मई, 1990

[मुख्य न्यायाधीश, सब्यसाची मुखर्जी, बी. सी. रे, एल. एम. शर्मा, पी. बी. सावंत

और के. रामास्वामी, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 341 और 342–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति–आरक्षण–क्या वह व्यक्ति जिसे मूल और जन्म राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में पुनर्निर्धारित किया गया है, उसे प्रवास राज्य में लाभ या विशेषाधिकार या अधिकार बने हुए हैं? 'उस राज्य के संबंध में' और 'इस संविधान के प्रयोजनों के लिए' अभिव्यक्तियों की व्याख्या में।

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति–महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति नहीं गौड़ा समुदाय–आवेदक जो आरक्षण के आधार पर सीट का दावा करने का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य के तेनाली में हुआ था और वह गौड़ा समुदाय से था, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि संविधान के तहत 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता प्राप्त। उनके पिता को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था और यह अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के आधार पर है कि उन्हें भारतीय उर्वरक निगम में और बाद में राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक, लिमिटेड में नियुक्त किया गया था, और बॉम्बे में 19.6.1978 से तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता भी नौ साल की उम्र से अपने पिता के साथ बॉम्बे में रह रहे थे और उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर 165 अंक प्राप्त करके 12 वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा प्राप्त की।

शैक्षणिक वर्ष 1989–90 के लिए उन्होंने बॉम्बे नगर निगम द्वारा संचालित तीन कॉलेजों में M.B.B.S पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया।

निगम और महाराष्ट्र राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए। याचिकाकर्ता को किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया था, हालांकि कुछ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जिन्होंने उनसे कम अंक प्राप्त किए थे, उन्हें प्रवेश दिया गया था। उन्हें प्रवेश देने से इनकार करने का कारण यह था कि वे अपने मूल और जन्म के अनुसूचित जनजाति के दर्जे के हकदार नहीं थे क्योंकि गौड़ा को महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए, यह न्यायालय, पकड़नाः समानता हमारे संविधान का आदेश है। अनुच्छेद 14 हमारे सभी नागरिकों के लिए अपनी पूर्णता में समानता सुनिश्चित करता है। राज्य को आदेश दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित न करे। हालाँकि, जहाँ असमान लोगों के बीच अवसर की वास्तविक समानता लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है, वहाँ कुछ

आरक्षण आवश्यक हैं और इन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संविधान के तहत समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसमें बराबरी की हर प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों के लिए समानता एक जीवित वास्तविकता बननी चाहिए। वास्तव में, जो असमान हैं, उनके साथ समान मानकों द्वारा व्यवहार नहीं किया जा सकता है; यह कानून में समानता हो सकती है लेकिन यह निश्चित रूप से वास्तविक समानता नहीं होगी। अवसर की समानता का अस्तित्व केवल अक्षमताओं की अनुपस्थिति पर ही नहीं बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। अपमानजनक समानता को अंततः वास्तविक समानता में अपना कारण खोजना चाहिए। [848 ई–जी। संतुलन उन लोगों के बीच किया जाना चाहिए जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, यानी जो लाभान्वित हैं। जातियाँ या जनजातियाँ और जो नहीं करते हैं। अनुच्छेद 341 और 342 के तहत निर्धारण को पूरे देश के लिए वैध मानना अनुच्छेद 15 (4) के साथ पठित अनुच्छेद 341 के उद्देश्य और योजना और भाषा के खिलाफ होगा। [855 सी–डी] संविधान में कुछ भी अधिशेष नहीं है और किसी भी हिस्से को निरर्थक नहीं बनाया जाना चाहिए। हालाँकि, संविधान के उद्देश्य और योजना को ध्यान में रखते हुए, जो न केवल एक मूल राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यायसंगत और निष्पक्ष होगी, बल्कि अन्य राज्यों में भी जहां अनुसूचित जातियाँ या जनजातियाँ अन्य जातियों या समुदाय के अधिकारों के अनुरूप प्रवास करती हैं, अधिकार सामंजस्यपूर्ण रूप से संतुलित होंगे। समाज के कमजोर वर्गों की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण को अपनाया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समुदाय के अन्य वर्गों की वैध अपेक्षाओं को बाहर न किया जाए। [858 ए–बी] याचिकाकर्ता इस आधार पर महाराष्ट्र में मेडिकल कर्नल में भर्ती होने का हकदार नहीं है कि वह अनुसूचित जाति का था। आंध्र प्रदेश में जनजाति। अधिवास के रूप में याचिकाकर्ता के प्रवेश के अधिकार का प्रश्न विचार के लिए नहीं आता है।

मौलिक न्यायनिर्णयः 1989 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 989।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)।

याचिकाकर्ता की ओर से राजू रामचंद्रन, श्रीमती साधना रामचंद्रन और रविंदर भट्ट।

सोली जे. सोराबजी, महान्यायवादी, एस. के. ढोलकिया। आर. पी. भट्ट, ए. एस. बोबडे, वी. ए. गंगल, ए. एस. भासमे, सुश्री ए. सुभाशिनी, वी. एन. उत्तरदाताओं के लिए गणपुले और एस. सुकुमारन।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सब्यसाची मुखर्जी, सीजे. इस रिट याचिका में शामिल मुद्दे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत देश और लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। समस्या को नियंत्रित करने में जो सिद्धांत लागू होने चाहिए, वे निर्विवाद हैं। हालाँकि, उनका अनुप्रयोग कुछ मात्रा में चिंता प्रस्तुत करता है।

इस याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता, भारत के नागरिक, का जन्म 6 अक्टूबर, 1969 को आंध्र प्रदेश राज्य के तेनाली में हुआ था। वह गौड़ा समुदाय, जिसे "गौडू" के नाम से भी जाना जाता है, के हैं। इस समुदाय को संविधान में 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी गई है।

(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, जैसा कि अब तक संशोधित है। हम इस आवेदन में इस पहलू पर तथ्यात्मक स्थिति की शुद्धता या अन्यथा से चिंतित नहीं हैं। याचिकाकर्ता के पिता को 3 अगस्त, 1977 को तहसीलदार, तेनाली, आंध्र प्रदेश द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर, याचिकाकर्ता के पिता को 17 अक्टूबर, 1977 को भारतीय उर्वरक निगम, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त किया गया था।

अनुसूचित जनजाति का कोटा। 19 जून, 1978 को, याचिकाकर्ता का पिता अनुसूचित के लिए आरक्षित कोटे के तहत भारत के एक सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में शामिल हुए।

याचिकाकर्ता, इसलिए, राज्य में बॉम्बे में रहने के लिए आया था महाराष्ट्र, नौ साल की उम्र से। याचिकाकर्ता ने अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा बॉम्बे में पूरी की। मार्च, 1989 में, याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र की 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की।

राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, बॉम्बे डिवीजनल बोर्ड ने कुल मिलाकर 165 अंक हासिल किए भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित। शैक्षणिक वर्ष 1989–90 के लिए, याचिकाकर्ता ने तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया।

बॉम्बे जो बॉम्बे नगर निगम द्वारा संचालित हैं (प्रतिवादी संख्या 2) और महाराष्ट्र राज्य द्वारा संचालित बॉम्बे में एक मेडिकल कॉलेज के लिए (प्रतिवादी संख्या 3)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों की कुल संख्या [1990] 2 एस. सी. आर. नगर निगम द्वारा संचालित तीन मेडिकल कॉलेजों में सीटें एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के लिए 400 सीटें हैं जिनमें से 7 प्रतिशत यानी 28 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं। महाराष्ट्र राज्य द्वारा संचालित माध्यमिक महाविद्यालय में कुल सीटों की संख्या 200 है, जिसमें से 7 प्रतिशत यानी 14 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की और अनुसूचित जाति के पक्ष में आरक्षण का लाभ उठाया जनजातियाँ। हालाँकि याचिकाकर्ता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया था बॉम्बे नगर निगम द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में से किसी एक में राज्य या महाराष्ट्र राज्य, हालांकि निर्विवाद रूप से अनुसूचित जनजाति जिन उम्मीदवारों ने उनसे कम अंक प्राप्त किए थे, उन्हें प्रवेश दिया गया था।

याचिकाकर्ता को प्रवेश से इनकार करने का निर्विवाद कारण था कि याचिकाकर्ता अपने अनुसूचित जनजाति के दर्जे का हकदार नहीं था मूल, जिसमें इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950। 22 फरवरी, 1985 को एक परिपत्र जारी किया गया है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय जो, अन्य बातों के साथ–साथ, कहते हैंः

" यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्ति जो शिक्षा, रोजगार आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से मूल राज्य से किसी अन्य राज्य में चला गया है, उसे अपने मूल राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति माना जाएगा और वह मूल राज्य से लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, न कि उस राज्य से जिसमें वह जाता है। पलायन किया है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र भी जैसा कि सरकार 15 साल के "अधिवास" की आवश्यकता का संकेत देती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है 1978 से 10 साल से अधिक समय तक महाराष्ट्र में रहे। यह मुद्दा, हालाँकि, इस रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह थी समस्या इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया। काउंटर में–पर दायर हलफनामा महाराष्ट्र राज्य की ओर से, आपत्ति व्याख्या पर थी संविधान के अनुच्छेद 342 का गठन और कोई विवाद नहीं था अधिवास के सवाल पर उठाया गया। इसलिए, यह उल्लेख करना आवश्यक है अनुच्छेद 342। संविधान का अनुच्छेद 342 इस प्रकार हैः

" 342. अनुसूचित जनजातियाँः (i) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है। जी. एस. मेडिकल कॉलेज (मुखर्जी, सीजे।)

जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या संघ के संबंध में अनुसूचित जनजाति मानी जाएगी। क्षेत्र, जैसा भी मामला हो। (2) संसद विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर या समूह के भाग को शामिल या बहिष्कृत कर सकती है, लेकिन उपरोक्त खंड के अधीन जारी अधिसूचना के अलावा, किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में, अनुच्छेद 341 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक हो सकता है क्योंकि यह अनुसूचित जातियों से संबंधित हैः

" 341. अनुसूचित जाति (1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए –

उस राज्य या संघ राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियाँ टोरी, जैसा भी मामला हो सकता है।

(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति, वंश या जनजाति या किसी जाति, जाति या जनजाति के भीतर के भाग या समूह को शामिल या बहिष्कृत कर सकती है, लेकिन उपरोक्त के अलावा –

उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना में किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा बदलाव नहीं किया जाएगा।

इसलिए इस मामले में यह सवाल उठता है कि क्या याचिकाकर्ता राज्य में अनुसूचित जनजाति होने के लाभ का दावा कर सकता है। हालाँकि महाराष्ट्र के, जैसा कि वे कहते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य में एक अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र था? चूंकि हम इस आवेदन में इस विवाद के साथ सहमत नहीं हैं कि क्या याचिकाकर्ता सही ढंग से या उचित रूप से गौड़ा समुदाय से संबंधित है या नहीं, या क्या याचिकाकर्ता के पास उचित प्रमाण पत्र था, इसलिए विवाद को मूल प्रश्न तक सीमित रखना वांछनीय है, अर्थात्, क्या वह व्यक्ति जो अपने मूल और जन्म के राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, उसे प्रवास की स्थिति में या जहां वह बाद में जाता है, वहां लाभ या विशेषाधिकार या अधिकार बने हुए हैं।

इस संबंध में, 848 के अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधान संविधान का संज्ञान लिया गया है। इन अनुच्छेदों में आदेश दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, जहां राज्य संबंधित हैं, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदाय या जनजातियों या आदिवासी समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। इसलिए मुख्य प्रश्न अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति द्वारा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के हिस्से के लिए, जैसा भी मामला हो, विनिर्देशन है। लेकिन यह विनिर्देशन 'इस संविधान के प्रयोजनों के लिए' है। इसलिए, जैसा कि प्रचार किया गया है, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि 'इस संविधान के उद्देश्यों के लिए' के संयोजन में 'उस राज्य के संबंध में' अभिव्यक्ति क्या व्यक्त करना चाहती है।

संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव को प्रतिबंधित करता है –

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। तथापि, अनुच्छेद 15 (4) में यह आदेश दिया गया है कि उस अनुच्छेद या संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए प्रावधान। इसलिए, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण या

अनुसूचित जातियों को सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों की उन्नति के उद्देश्य से उन्हें शैक्षिक या नौकरी की सुविधाओं में समुदाय के अन्य वर्गों के बराबर बनाने के लिए संविधान का अधिदेश है। समानता हमारे संविधान का आदेश है। अनुच्छेद 14 हमारे सभी नागरिकों के लिए अपनी पूर्णता में समानता सुनिश्चित करता है। राज्य को आदेश दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित न करे। हालाँकि, जहाँ असमान लोगों के बीच अवसर की वास्तविक समानता लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है, वहाँ कुछ आरक्षण आवश्यक हैं और इन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संविधान के तहत समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसमें बराबरी की हर प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। बड़ी

संख्या में लोगों के लिए समानता एक जीवित वास्तविकता बननी चाहिए। वास्तव में, जो असमान हैं, उनके साथ समान मानकों द्वारा व्यवहार नहीं किया जा सकता है; यह कानून में समानता हो सकती है लेकिन यह निश्चित रूप से वास्तविक समानता नहीं होगी। अवसर की समानता का अस्तित्व केवल क्षमताओं के अभाव पर ही नहीं बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। यह केवल कानूनी समानता का मामला नहीं है। न्यायिक समानता को अंततः वास्तविक समानता में अपना कारण खोजना चाहिए। इसलिए, राज्य को उन लोगों को, जो वास्तव में अपनी संपत्ति, शिक्षा या सामाजिक वातावरण में असमान हैं, निर्दिष्ट क्षेत्रों में समान बनाने के उद्देश्य से प्रतिपूरक राज्य कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए। समाज में मौजूद वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखना और एम. सी. एस. आर. ए. ओ. बनाम को प्राथमिकता देकर सकारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है।

जी. एस. मेडिकल कॉलेज [मुखर्जी, सी. जे.] और वास्तविक समानता लाने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को आरक्षण या अधिक लाभप्रद लोगों पर बाधाएं डालना। इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई, हालांकि स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है, वास्तविक असमानताओं को समाप्त करके और समुदाय के कमजोर वर्गों को मजबूत और अधिक शक्तिशाली वर्गों के साथ समानता के आधार पर रखते हुए व्यापक आधार पर समानता पैदा करने के लिए गणना की जाती है ताकि समुदाय का प्रत्येक सदस्य, चाहे उसका जन्म, व्यवसाय या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अपने शारीरिक, चरित्र और बुद्धि के प्राकृतिक दान का पूरी तरह से उपयोग करने का समान अवसर प्राप्त कर सके। इस संबंध में, प्रदीप जैन और अन्य मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है। वी. भारत संघ और अन्य। , [1984] 3 एससीसी 654।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक नुकसान का सामना करना पड़ा और उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ा विकास और विकास की सुविधाएँ। इसलिए, यह आवश्यक है कि उन्हें उन क्षेत्रों में समान बनाया जाए जहां वे इस तरह से पीड़ित हैं और विकास की स्थिति में हैं, आरक्षण या उनके पक्ष में संरक्षण ताकि वे समुदाय के अधिक लाभप्रद या विकसित वर्गों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथाओं से उत्पन्न चरम सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को आम तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक समुदाय को शामिल करने के लिए मानदंड माना जाता है। हालाँकि, एक जाति की सामाजिक स्थितियाँ राज्य से राज्य में भिन्न होती हैं और पूरे देश के लिए किसी भी जाति या किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के रूप में सामान्यीकृत करना उचित नहीं होगा। यह, चाहे जो भी हो, एक अलग समस्या है कि क्या देश के एक हिस्से में अनुसूचित जाति का कोई सदस्य जो दूसरे राज्य या किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास करता है, उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाना चाहिए जिसमें वह प्रवास कर चुका है। उस प्रश्न का निर्णय पूरे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति बेहतर या अधिक सामाजिक रूप से स्वतंत्र स्थान पर प्रवास करके अपनी जाति से संबंधित होना बंद नहीं करता है और उदार वातावरण। लेकिन अगर सामाजिक रूप से उन्नत क्षेत्र में पर्याप्त समय बिताया जाता है तो सामाजिक रूप से वंचित समुदाय से संबंधित होने से होने वाले अवरोध और बाधाएं जारी नहीं रहती हैं और एक पुरुष या महिला या एक लड़के या लड़की की प्राकृतिक प्रतिभा को फलने–

फूलने की पूरी गुंजाइश मिलती है। हालाँकि, ये सामाजिक समायोजन की समस्याएं हैं अर्थात सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के एक निश्चित वर्ग को कितनी दूर तक सुरक्षा दी जानी चाहिए और कितने समय तक दूसरों के बराबर होना नाजुक सामाजिक समायोजन का विषय है। ये [1990] 2 एस. सी. आर. में इतने संतुलित होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट देश की अखंडता का मोज़ेक जो किसी भी वर्ग या समुदाय को नहीं करना चाहिए अन्य समुदाय या कॉम के हिस्से को नुकसान या असंतोष पैदा करना सामूहिकता या अनुभाग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश के किसी विशेष क्षेत्र को तब तक सुरक्षा दी जानी चाहिए जब तक कि वे इसके बराबर होने के हकदार हैं। अन्य। लेकिन समान रूप से अन्य क्षेत्रों में जाने वालों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समुदाय के उस हिस्से के वंचित और विकलांग लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं जो उन क्षेत्रों में अक्षमताओं से पीड़ित हैं। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कहना है कि आंध्र प्रदेश को अन्य समुदायों के बीच संतुलित रूप से आवश्यक सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन समान रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कहना है कि तत्काल मामले में महाराष्ट्र को महाराष्ट्र राज्य में सुरक्षा की आवश्यकता है, जो अन्य समुदायों के लिए संतुलन में होनी चाहिए। यह समस्या का मूल दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि कोई इस बुनियादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है, तो विवाद का निर्धारण

तत्काल मामला मुश्किल नहीं होता है। समस्या को समझने के उद्देश्य से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश विधेयक, 1967 पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट को संदर्भित करना सार्थक हो सकता है। 17 सितंबर, 1949 को संविधान सभा की कार्यवाही का उल्लेख करना भी उपयुक्त हो सकता है, जो बाद में अनुच्छेद 303 और 304 से संबंधित थी। यह क्रमशः अनुच्छेद 341 और 342 बन गया। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहाः

" कि अनुच्छेद 300 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेदों को जोड़ा जाएः

300 ए (1) राष्ट्रपति, उनसे परामर्श करने के बाद, किसी राज्य के राज्यपाल या शासक, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें जातियाँ, जातियाँ या जनजातियाँ या जातियों के भीतर के भाग या समूह जातियाँ या जनजातियाँ, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति मानी जाएगी।

(2) संसद कानून द्वारा इसमें शामिल या बहिष्कृत कर सकती है – द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची इस अनुच्छेद के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति को कोई भी जाति, नस्ल या किसी भी जाति, जाति या जनजाति के भीतर जनजाति या उसका हिस्सा या समूह, लेकिन उपरोक्त के रूप में उक्त के तहत जारी एक अधिसूचना को सहेजें खंड में किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

300 बी. (1) राष्ट्रपति के साथ विचार–विमर्श के बाद किसी राज्य के राज्यपाल या शासक, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या उनके भाग या समूह जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय जो इसके उद्देश्यों के लिए होंगे। संविधान को संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाए उस राज्य में।

(2) संसद कानून द्वारा इस अनुच्छेद के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर या समूह के हिस्से को शामिल या बाहर कर सकती है, लेकिन उपरोक्त अधिसूचना के अलावा।

उक्त खंड के तहत जारी किए गए किसी भी द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा बाद की अधिसूचना। इन दो अनुच्छेदों का उद्देश्य, जैसा कि मैंने कहा, संविधान पर बोझ डालने की आवश्यकता को समाप्त करना था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लंबी सूची। अब यह प्रस्तावित किया गया है कि राष्ट्रपति, के परामर्श से किसी राज्य के राज्यपाल या शासक के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि – राजपत्र में अनुसूचित मानी जाने वाली सभी जातियों और जनजातियों या समूहों को निर्दिष्ट करते हुए एक सामान्य अधिसूचना जारी करें। जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्देश्यों के लिए विशेषाधिकार जो संविधान में उनके लिए परिभाषित किए गए हैं। एकमात्र सीमा जो लगाई गई है वह यह हैः कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद, जो निस्संदेह, वह प्रत्येक राज्य की सरकार के परामर्श से और उसकी सलाह पर जारी करेगा, उसके बाद, यदि इस प्रकार अधिसूचित सूची से कोई उन्मूलन किया जाना था या कोई जोड़ किया जाना था, तो वह संसद द्वारा किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रपति द्वारा। इसका उद्देश्य इस प्रकार प्रकाशित अनुसूची में गड़बड़ी के मामले में किसी भी प्रकार के राजनीतिक कारकों को समाप्त करना है।"

प्रो. के विचारों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। के. टी. शाह ने अपनी विधानसभा में जो इस प्रकार हैंः

" कि अनुच्छेद 9 के खंड (2) के अंत में, निम्नलिखित होगा जोड़ा गयाः

' या अनुसूचित जातियों या पिछड़े जनजातियों के लिए, उनके लिए लाभ, सुरक्षा या बेहतरी '

खंड, जैसा कि है, इस प्रकार हैः " इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्यों को 2 एस. सी. आर. बनाने से नहीं रोकेगी। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करना। महोदय, इसे पिछले लेख से अलग किया जाना चाहिए। कम से कम, मैंने पढ़ा कि यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में भेदभाव का प्रावधान है, जिसमें मैंने अनुसूचित जातियों या पिछड़ी जनजातियों को जोड़ा है। यह अपराध हमारे समाज के विशेष वर्गों के पक्ष में है, जो अतीत की दुर्भाग्यपूर्ण विरासत के कारण विकलांगों या विकलांगों से पीड़ित हैं। जिन्हें, मुझे लगता है, आवश्यकता हो सकती है विशेष व्यवहार; और यदि उन्हें इसकी आवश्यकता है, तो उन्हें कुछ समय के लिए विशेष सुविधाओं की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि नागरिकों की वास्तविक समानता स्थापित की जा सके। समानता के लिए आक्रोश, जिसके कारण महिलाओं के लिए समान नागरिक अधिकार और समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, कभी–कभी विशेष प्रावधानों के संबंध में अपवाद पाया गया है, जो देश या जाति के हित में लंबे समय तक महिलाओं को कुछ खतरनाक व्यवसायों, कुछ प्रकार के काम से बाहर रखते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी तरह से उनकी नागरिक समानता या नागरिक के रूप में स्थिति को कम करने का इरादा नहीं है। इसका उद्देश्य केवल उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना या सामान्य रूप से उनकी बेहतरी के लिए नेतृत्व करना है ताकि देश के दीर्घकालिक हितों को नुकसान न पहुंचे।

अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जनजातियों के संबंध में, यह एक खुला रहस्य है कि अतीत में उनकी उपेक्षा की गई है और उनके पिछड़ेपन के कारण समान नागरिकों के रूप में आनंद लेने और आनंद लेने की क्षमता रखने के उनके अधिकारों और दावों से उन्हें वंचित किया जाता है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें भी इस उपखंड (2) के दायरे में शामिल करने का अनुरोध करता हूं, ताकि उनके पक्ष में किसी भी विशेष भेदभाव को देश के सभी वर्गों के नागरिकों के लिए समानता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं माना जा सके। वे रोजगार के लिए अवसर, और कई अन्य मामलों में जहां उनकी वर्तमान असमानता, उनकी वर्तमान पिछड़ेपन केवल तेजी से विकास के लिए एक बाधा है देश। समुदाय का कोई भी वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, उसे ऐसा करना चाहिए अनिवार्य रूप से बाकी की प्रगति में बाधा डालना; और इसलिए यह केवल समुदाय के हित में है कि यह केवल है। सही और उचित हमें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि वे कहने के लिए अप–टू–डेट लाया जा सकता है और वर्दी पेशेवर सभी को अग्रेषित किया जाए। बेशक, मैंने अपने संशोधन में शामिल नहीं किया है वर्षों की अवधि जिसके लिए कुछ ऐसे विशेष उपचार दिया जा सकता है। यह निर्धारित किया जा सकता है दिन की परिस्थितियों में। मैं केवल आपको आकर्षित करना चाहता हूँ इस तथ्य पर ध्यान दें कि हमारे नागरिकों के वर्ग हैं जिन्हें उनकी कोई गलती नहीं होने के कारण कुछ विशेष की आवश्यकता हो सकती है यदि समानता केवल नाम की समानता नहीं है या केवल कागज पर, लेकिन तथ्य की समानता। मुझे विश्वास है कि यह आएगा। सदन में खुद को सुधारें और संशोधन होगा स्वीकार कर लिया "। हालाँकि, अभिव्यक्तियों को उचित अर्थ देना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में उल्लिखित इस संविधान के प्रयोजनों के लिए और उस राज्य के संबंध में। गुजरात उच्च न्यायालय ने दो निर्णयों में विचार लिया है, अर्थात्, कुम। मंजू सिंह बनाम। डीन, बी. जे. मेडिकल कॉलेज, ए. आई. आर. 1986 गुजरात 175 और घनश्याम किसान बोरिकर बनाम। एल. डी. इंजीनियरिंग कॉलेज, आकाशवाणी 1987 गुजरात 83 जिस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, वह वाक्यांश ' इस संविधान के प्रयोजनों के लिए 'उस राज्य के संबंध में' वाक्यांश के अधीन नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए और इसके पहले, उन दो निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि परिणामस्वरूप एक राज्य द्वारा किसी विशेष जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखने के लिए किया गया वर्गीकरण – उस जाति या जनजाति के सदस्य को भारत के संविधान के तहत सभी लाभों, विशेषाधिकारों और संरक्षणों के लिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एम. मुनि रेड्डी बनाम के मामले में भी ऐसा ही विचार रखा है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य। , [1981] प्रयोगशाला। आई. सी. 1345। दूसरी ओर, के. अप्पा राव बनाम के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय। डाक और तार निदेशक, उड़ीसा और अन्य। , ए. आई. आर. 1969 उड़ीसा 220 और एम. एस. मालथी बनाम में बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ। आयुक्त, नागपुर प्रभाग और अन्य। , ए. आई. आर. 1989 बॉम्बे 138 का विचार है कि अनुच्छेद 341 और 342 में आने वाली 'उस राज्य के संबंध में' अभिव्यक्ति को देखते हुए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केवल उस राज्य में उपलब्ध होगी जिसके संबंध में जाति या जनजाति इस प्रकार निर्दिष्ट है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वी. बी. सिंह बनाम के मामले में भी ऐसा ही विचार रखा है। पंजाब राज्य, आईएलआर 1976 1 पंजाब और हरियाणा 769। यह सामान्य ज्ञान है कि वैधानिक और संवैधानिक प्रावधान [1990] 2 एस. सी. आर.सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सायन की व्याख्या व्यापक रूप से और सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए। यह कहना तुच्छ है कि जहां दो प्रावधानों के बीच टकराव है, उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए ताकि दोनों को प्रभावी बनाया जा सके। संविधान में कुछ भी अधिशेष नहीं है।

यह और किसी भी भाग को नुकीला नहीं बनाया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है। श्री वेंकटरमण देवरू और अन्य में इस न्यायालय की टिप्पणियों को देखें। वी. मैसूर राज्य और अन्य। , [1958] 918 में एस. सी. आर. 895, जहां न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर ने दोहराया कि निर्माण का नियम अच्छी तरह से स्थापित है और जहां एक अधिनियम में दो प्रावधान हैं जिनका एक–दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि, यदि संभव है, दोनों को प्रभाव दिया जा सकता है। तथापि, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 341 के साथ–साथ अनुच्छेद 342 में 'इस संविधान के प्रयोजनों के लिए' अभिव्यक्ति का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार निर्दिष्ट अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ उन सभी संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठाने की हकदार होंगी जो सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। संवैधानिक अधिकार, उदाहरण के लिए, यह तर्क दिया गया है कि प्रवास का अधिकार या एक भाग से दूसरे भाग में जाने का अधिकार सभी को–अनुसूचित जातियों या जनजातियों और गैर–अनुसूचित जातियों या जनजातियों को दिया गया अधिकार है। लेकिन जब कोई अनुसूचित जाति या जनजाति प्रवास करती है, तो प्रवास करने में कोई रोक नहीं है, लेकिन जब वह प्रवास करता है, तो वह उस राज्य या क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए निर्दिष्ट मूल राज्य में उसे दिए गए या उसे दिए गए किसी विशेष अधिकार या विशेषाधिकार को नहीं रखता है और न ही ले सकता है। यदि वह अधिकार प्रवासी राज्य में नहीं दिया जाता है तो यह उसके समानता या प्रवास के या अपने व्यापार, व्यवसाय या पेशे को जारी रखने के संवैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। न तो अनुच्छेद 14,16,19 और न ही अनुच्छेद 21 को प्रवास द्वारा अस्वीकार किया गया है, लेकिन उसे कानून के अनुसार उन अधिकारों का आनंद लेना चाहिए यदि उनका पालन उस स्थान पर किया जाता है जहां वह प्रवास करता है। यह तर्क दिया गया था कि एकमात्र तरीका जिसमें मौलिक अधिकार याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 14,19 (1) (डी), 19 (1) (ई) और 19 (1) (एफ) के तहत अनुच्छेद 342 का अर्थ इस तरह से लगाया जा सकता है कि –अनुसूचित जनजाति के सदस्य को पूरे भारत के क्षेत्र में संविधान के उद्देश्यों के लिए उस स्थिति का लाभ मिलता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि "इस संविधान के उद्देश्यों के लिए" शब्दों को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। "इस संविधान के प्रयोजनों के लिए" शब्दों का अर्थ यह होना चाहिए कि इस प्रकार नामित अनुसूचित जाति को अनुच्छेद 14,19 (1) (डी), 19 (1) (ई) और 19 (1) (एफ) के तहत अधिकार होना चाहिए क्योंकि ये उसके उस क्षेत्र में लागू होते हैं जहां वह प्रवास करता है या जहां वह जाता है। "उस राज्य के संबंध में" अभिव्यक्ति निरर्थक हो जाएगी यदि सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विशेष विशेषाधिकार या अधिकार एम. सी. एस. आर. ए. ओ. बनाम.आगे बढ़ें। यह आरक्षण की योजना के पूरे उद्देश्य के साथ भी असंगत होगा। आंध्र प्रदेश में, एक अनुसूचित जाति या एक अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि उस क्षेत्र में बढ़ने वाला एक लड़का या बच्चा बाधित है या नुकसान में है। महाराष्ट्र में उस जाति या उस जनजाति को इतना बाधित नहीं किया जा सकता है लेकिन अन्य जातियाँ या जनजातियाँ हो सकती हैं। अगर कोई लड़का या बच्चा उस वातावरण में जाता है महाराष्ट्र में एक छोटे लड़के या एक बच्चे के रूप में और पूरी तरह से

अलग किराए के माहौल में जाता है या महाराष्ट्र में जहां यह अवरोध या इस तरह की सुविधा नहीं है, तो उसे ऐसा आरक्षण नहीं कहा जा सकता है जो बच्चों या उस राज्य के किसी भी वर्ग से संबंधित महाराष्ट्र के लोगों को वंचित कर दे, जिन्हें अभी भी उस सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार, यह ध्यान में रखना होगा कि महाराष्ट्र की वंचित जातियों या जनजातियों के साथ–साथ वंचितों के लिए भी सुरक्षा आवश्यक है आंध्र प्रदेश की सुविधाजनक जातियाँ या जनजातियाँ। इस प्रकार, उन लोगों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, यानी, जो लाभान्वित जातियों या जनजातियों से संबंधित हैं और जो नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत निर्धारण को पूरे देश के लिए वैध मानना अनुच्छेद 341 के उद्देश्य और योजना और भाषा के लिए नकारात्मक होगा। संविधान का अनुच्छेद 15 (4)। एलिजाबेथ [1990] 2 एस. सी. आर. में कुछ टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। वारबर्टन बनाम। जेम्स लवलैंड, [1832] हाउस ऑफ लॉर्ड्स 499। यह सच है कि सभी प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। यह भी सच है कि किसी भी प्रावधान को इस तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि वह अन्य प्रावधानों को निरर्थक या प्रतिबंधित बना दे। लेकिन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण का आदेश है कि हमें प्रत्येक अभिव्यक्ति को–'उस राज्य के संबंध में' या 'इस संविधान के उद्देश्यों के लिए'–इसका पूरा अर्थ देना चाहिए और उनका पूरा प्रभाव देना चाहिए। इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि एक को दूसरे को नकारना नहीं चाहिए। यह निर्माण कि उस राज्य की अनुसूचित जाति या जनजाति के संबंध में दिया गया आरक्षण उस राज्य में संविधान के तहत सभी विशेषाधिकारों और अधिकारों का हकदार होने के लिए इस तरह से निर्धारित है, संविधान की भाषा, उद्देश्य और योजना के अनुरूप पढ़ने का सबसे सही तरीका होगा। अन्यथा, यह ध्यान में रखना होगा कि यदि आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में माने जाने वाले लड़कों या लड़कियों को भी आरक्षण दिया जाता है, जो महाराष्ट्र राज्य या अन्य राज्यों में पलायन करते हैं और कट जाते हैं, जहां उस जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं माना जाता है, तो किसी भी आरक्षण का प्रभाव महाराष्ट्र में उस जाति या जनजाति के सदस्य को प्रतिशत से वंचित करने का होगा जो संरक्षण का हकदार होगा या यह महाराष्ट्र में अन्य गैर–अनुसूचित जाति या गैर–अनुसूचित जनजाति को उस अनुपात से वंचित कर देगा जिसके वे हकदार हैं। यह संविधान द्वारा परिकल्पित तार्किक या सही परिणाम नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रदीप जैन बनाम के मामले में। भारत संघ, (ऊपर), यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर सीटों का थोक आरक्षण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। समान रूप से यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 342 का निर्माण जो आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत चिकित्सा सीट प्राप्त करने से पूरी तरह से रोकता है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सभी लाभों का हकदार होगा। यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 19 (1) (डी), (ई) और (एफ) के तहत, यदि कोई माता–पिता अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो विपरीत दृष्टिकोण होगाअनिवार्य रूप से इसका मतलब यह है कि उसे अपनी शिक्षा, अनुभव और प्रतिभा के अनुरूप सभी उपयुक्त नौकरी के अवसरों की उपेक्षा करते हुए अपने

गृह राज्य तक ही सीमित रहना चाहिए। हम इस अधीनता को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ये अतिरिक्त संरक्षण नहीं हैं, यानी वह केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा का आनंद ले सकता है, लेकिन वह मौजूदा मौलिक अधिकारों के अलावा गैर–अनुसूचित जनजाति या जातियों की सुरक्षा का आनंद नहीं ले सकता है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दृष्टिकोण की ओर से प्रचार किया गया है याचिकाकर्ता को भारत के संविधान पर दुर्गा दास बसु की टिप्पणी, 6 वें संस्करण, खंड में समर्थन मिलता है। एन–पृष्ठ 149, जहाँ यह निम्नानुसार कहा गया हैः

" उस राज्य के संबंध में '। 1. एक जाति जिसे के रूप में निर्दिष्ट किया गया है किसी विशेष राज्य में अनुसूचित जाति होने के योग्य नहीं हो सकती है इस प्रकार किसी अन्य राज्य में निर्दिष्ट। लेकिन जब एक जाति निर्दिष्ट की जाती है किसी विशेष राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश में, यह इसका मतलब यह नहीं है कि उस जाति के व्यक्ति को केवल उसी के लिए एस. सी. का सदस्य माना जाए। अकेले राज्य करें। एक बार अनुसूचित जाति में एक जाति को शामिल किया जाता है जाति आदेश, जो कि उद्देश्यों के लिए होगा संविधान। ”

यह इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रस्तुत किया गया था प्रदीप जैन का मामला (ऊपर) कि 15 साल के निवास की आवश्यकता महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए

यह पूरी तरह से मनमाना, अनुचित है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। डी. पी. जोशी बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। मध्य भारत और अन्न राज्य। , [1955] 1 एससीआर 1215 और माइनर पी. राजेंद्र बनाम। मद्रास राज्य और अन्य। , [1968] 2 एससीआर 786 निवास योग्यता के प्रश्न पर। इस दृष्टि से हम तत्काल मामले में विवाद के संदर्भ में, हम एम. सी. एस. आर. ए. ओ. बनाम हैं। यह राय कि यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं होगा।

हमने भारत के विद्वान महान्यायवादी को सुना है और उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। नीति निम्नानुसार प्रतीत होती हैः

" ।. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित/प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों में अखिल भारतीय सेवाओं या प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वे किसी भी राज्य से संबंधित हों। भारत सरकार के तहत पदों और सेवाओं में रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में लागू आरक्षण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पुनर्भरण पर विवरणिका के अध्याय 2 में संलग्न है।
भारत सरकार द्वारा जारी की गई सेवाएँ)। अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण इन प्रावधानों द्वारा कवर किए जाते हैं और पहले भेजे जाने

पर क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत होते हैं। केंद्रीय सरकार/सरकारी सेवाओं में अखिल भारतीय सेवाएँ अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, वन सेवा आदि शामिल हैं।

II. अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में सीधी भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती क्रमशः 15 और 7.5 के इंगित प्रतिशत पर राज्यों को आवंटित की जाती है। कैडर अंतर और प्रत्यक्ष भर्ती कोटे में आसन्न सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को आवंटित किया जाने वाला कोटा या अधिकारियों की संख्या पहले से तय की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में 12 सीधी रिक्तियां हैं, तो उनमें से 22.5% 2.7 होगा। उस स्थिति में, 2.70 को 3 में विभाजित किया जाएगा और उस राज्य संवर्ग को आरक्षित श्रेणी से संबंधित 3 अधिकारी आवंटित किए जाएंगे। हालाँकि, यह वर्तमान विवाद को प्रभावित नहीं करता है। हमें महाराष्ट्र के महाधिवक्ता श्री ए. एस. बोबडे को सुनने का भी लाभ मिला। याचिकाकर्ता के वकील श्री राजू रामचंद्रन ने हमारे समक्ष संविधान के बारे में समग्र दृष्टिकोण रखने का आग्रह किया। वास्तव में, वह सही हैं कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

तथापि, उद्देश्य और योजना को ध्यान में रखते हुए ऐसा संविधान जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो, न केवल एक मूल राज्य का बल्कि अन्य राज्यों में भी जहां अनुसूचित जातियां या जनजातियां अन्य जातियों या समुदाय के अधिकारों के अनुरूप प्रवास करती हैं, अधिकारों को सामंजस्यपूर्ण रूप से संतुलित किया जाना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण को अपनाया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समुदाय के अन्य वर्गों की वैध अपेक्षाओं को बाहर न किया जाए। व्याख्या पर हम उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं। संबंधित प्रावधानों के बारे में। इस संबंध में, यह नहीं हो सकता है उत्पन्न होने वाली समस्या की संभावनाओं के बारे में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के विचारों का उल्लेख करना अनुचित है, जिन्होंने कॉन में कहा था।

श्री जय पाल सिंह ("अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सुरक्षा उपाय") द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में स्थितिजन्य बहस एच. एस. सक्सेना द्वारा "संस्थापक पिता का दृष्टिकोण", पी. 60) जिनका प्रभाव निम्नलिखित हैः

" उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछा और वह यह था। मान लीजिए। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जनजाति का सदस्य भारत के क्षेत्र के दूसरे हिस्से में प्रवास करता है, जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र दोनों के बाहर, क्या वह स्थानीय सरकार से दावा करने में सक्षम हो, जिसके भीतर वह अधिकार क्षेत्र में रह रहा हो सकता है, वही विशेषाधिकार जो वह तब हकदार होगा जब वह इसके भीतर रह रहा होगा अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र के भीतर? यह मुश्किल है मुझे जवाब देने के लिए सवाल। अगर यह मामला भड़का हुआ है इस संविधान के किसी खंड के रूप में प्रश्न। लेकिन, जहाँ तक वर्तमान संविधान का संबंध है, एक सदस्य अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति से बाहर जाने वाली अनुसूचित जनजाति विशेषाधिकार जिनका वह तब हकदार है जब वह किसी राज्य

में रह रहा हो। अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ; यह होगा लागू होने वाले प्रावधानों को लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है जनजातीय क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो उनके द्वारा कवर किए जाते हैं मामले के उस दृष्टिकोण से, हमारी राय है कि

याचिकाकर्ता महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का हकदार नहीं है। विचार में हम याचिकाकर्ता के अधिवास के रूप में भर्ती होने के अधिकार का सवाल विचार के लिए नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों को समझने के बाद, अगला सवाल जो विचार के लिए आता है, वह है उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के भाग्य का सवाल, जिन्हें मूल राज्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत होने का संरक्षण मिलता है, जब –

अपने पिता या अभिभावक के व्यवसाय या सेवा के स्थानांतरण या आवाजाही के कारण, वे स्वैच्छिक हस्तांतरण के रूप में अन्य राज्यों में चले जाते हैं, क्या वे किसी प्रकार के सुरक्षात्मक व्यवहार के हकदार होंगे ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें या आगे बढ़ सकें। ऐसी स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन अनैच्छिक है, रोजगार या पेशे में से किसी एक के रुख के बल पर, ऐसे मामलों में यदि छात्र या व्यक्ति प्रवासित राज्य में आवेदन करते हैं, जहां उन राज्यों या क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को पूर्व–न्यायिक रूप से प्रभावित किए बिना, अध्ययन या प्रवेश जारी रखने के लिए कोई सुविधा या संरक्षण उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जो इस तरह से प्रवास कर चुका है, तो उस आधार पर कुछ सहमति बनाना वांछनीय है। इसलिए, विधानमंडलों या संसद के लिए यह आवश्यक और शायद वांछनीय होगा कि वे इस पहलू को ध्यान में रखते हुए उचित विधानों पर विचार करें ताकि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत प्रावधानों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अधिकारों को उचित प्रभाव दिया जा सके। यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानसभाएं या संसद उचित रूप से विचार कर सकती है।

वह इस आधार पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने का हकदार है कि वह अपने मूल राज्य में अनुसूचित जनजाति से है। हालाँकि, याचिकाकर्ता को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई में प्रगति की है। लेकिन उन्होंने एक वचन दिया था कि वह प्रशासन के आधार पर जोर नहीं देंगे। अगर हम उन्हें महाराष्ट्र के कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देते हैं, जहां उन्हें इस आवेदन में सफल नहीं होने के बाद दिए गए अंडरटेकिंग पर भर्ती कराया गया है, तो यह एक बुरी मिसाल होगी। लेकिन, हमें न्याय करना चाहिए। लड़के की शैक्षिक संभावनाओं को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि वह कुछ हद तक आगे बढ़ गया है और इस स्तर पर या इस वर्ष इस आधार पर उसे जीवनदान देना कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संरक्षण का हकदार नहीं है, अनुसूचित जातियों को कोई समान लाभ प्रदान नहीं करेगा या महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियाँ या उस मामले में किसी और पर। इसलिए यह सवाल वांछनीय है कि क्या वह वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1990] 2 एस. सी. आर. हैं।

गौड़ा समुदाय से संबंधित है और क्या यह समुदाय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, यह पहले ठीक से और उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, हमने इस प्रश्न की जांच नहीं की है। यह निर्धारित करने के बाद कि क्या महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान करने के बाद, यदि याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश या अध्ययन जारी रखने की कोई सुविधा दी जा सकती है, तो संस्थान के प्रभारी अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए और यदि इस पर विचार करते हुए वे याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देना उचित पाते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, उसी के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के सवाल पर विचार करते हुए, उपयुक्त अधिकारियों को स्थिति के न्याय को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम यह अधिकारियों पर छोड़ते हैं कि वे उपरोक्त विचार के आधार पर याचिकाकर्ता के अध्ययन को जारी रखने या बंद करने के बारे में उचित कार्रवाई करें। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। हम ऐसा केवल इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में करते हैं, और उपरोक्त टिप्पणियों को अन्य स्थितियों के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

इसलिए हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता होने का हकदार नहीं है मेडिकल कॉलेज में इस आधार पर भर्ती कराया गया कि वह आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ लेकिन कॉलेज में उनकी निरंतरता यह पहले बताए गए विचार पर निर्भर करेगा। द रिट इस प्रकार याचिका का निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आरएनजे

याचिका का निपटारा किया गया।